गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 028
दि. 28.05.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर

मोदी सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मुहैया करवा रही है. अब इस योजना में सरकार ने तीन बदलाव किए हैं. अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है.

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ है. कैबिनेट के इस फैसले से राशन लेने वाले 80 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ेगा. सरकार ने राशन व्यवस्था (ढऊ- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया. इसके लिए 'सार्थक-पीडीएस' (SARTHAK-PDS) योजना शुरू की गई है. इस पूरी योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

PDS स्कीम में तीन बड़े बदलाव

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करवाने का कार्यक्रम चल रहा है. इस सार्थक PDS स्कीम में तीन बदलाव किए गए हैं. इनमें राज्य सरकार को मदद करने की बात, टेक्नोलॉजी की मदद लेने की भी बात और AI के तहत अब PDS लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

बताया, 'राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बड़े गोदामों से अनाज को अलग-अलग जिलों, ब्लॉकों और आखिरी में राशन की दुकानों तक पहुंचाने में पैसों की दिक्कत आ रही थी. अब केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देगी.'

दूसरा बदलाव ये है कि राशन दुकानदारों (डीलर) का कमीशन बढ़ाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'राशन देने वाले डीलरों का कमीशन काफी समय से नहीं बढ़ा था. लगातार डीलर के कमीशन को बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी. आज सरकार ने उनकी इस मांग को मानते हुए उनका कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है.'

तीसरा और आखिरी बदलाव यह है कि पूरी राशन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक तथा पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नई टेक्नोलॉजी (तकनीक) का इस्तेमाल किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'सरकार इस भारी-भरकम बजट से राशन पहुंचाने का खर्च उठाएगी. दुकानदारों की कमाई बढ़ाएगी और पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाएगी.'

लू से निपटने के लिए सरकार की तैयारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'मौजूदा लू की स्थिति पर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की गई. प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को पहुंचाने के लिए कई ट्वीट किए गए. उस संदेश के जवाब में, उन खास कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें हर मंत्रालय और विभाग अपने-अपने दायरे में उठा सकता है.'

उन्होंने बताया, 'लू के दौरान भारत के नागरिकों को राहत देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें खास तौर पर उन सुविधाओं और उपायों पर ध्यान दिया गया जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जब इस तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना करना हो, तो हमें उनके प्रति 'पूरे राष्ट्र की भावना' के साथ आगे बढ़ना चाहिए.'

एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को, मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को दिल्ली में होगी। नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, विकास योजनाओं, केंद्र-राज्य समन्वय और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 10 जून को दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है।

मंत्रिपरिषद की बैठक: नौकरशाही को चाक-चौबंद करने की कवायद; ढट मोदी ने जाना किस स्तर पर कितने समय अटकती है फाइल

12 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी

बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल

होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र के कल्याणकारी और विकास एजेंडे के लिए जनसंपर्क को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श होगा।

चर्चा का केंद्र मोदी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी पहलों को जमीनी स्तर तक ले जाना भी होगा। राज्यों में लाभार्थियों को केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। इनमें कल्याण वितरण, बुनियादी ढांचा विकास और रोजगार सृजन शामिल हैं।

विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर बात

परिषद की बैठक में केंद्र और एनडीए शासित राज्यों के बीच समन्वय की समीक्षा की जाएगी। विकास कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। राज्यों के बीच शासन रणनीतियों को साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित होगा। यह बैठक गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक अभ्यास मानी जा रही है। इसका उद्देश्य एनडीए सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है।

आगामी विधानसभा चुनावों रोडमैप पर चर्चा

शासन और कल्याण संबंधी मुद्दों के अलावा, बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रोडमैप पर भी चर्चा हो सकती है। कई राज्यों में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के विकास के एजेंडे को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगी। 10 जून की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भाजपा और उसके सहयोगी केंद्र की नीतिगत पहलों को उजागर कर रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर शासन के रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला जा रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम थलापति विजय; हाथों में गुलदस्ता, चेहरे पर मुस्कान ...25 मिनट की मीटिंग से चढ़ेगा राजनीतिक पारा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख थलापति विजय ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा थी. करीब 25 मिनट चली इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. विजय ने प्रधानमंत्री को लंबित परियोजनाओं, वित्तीय सहायता और मेकेदातु जल विवाद समेत विह्वि

(जीएनएस)।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की यह टीवीके प्रमुख विजय की पहली आधिकारिक

यात्रा है.

दोनों नेताओं की इस मुलाकात की सामने आई तस्वीर को लेकर चचाओं का बाजार गरम है. थलापति विजय सिंपल ब्लैक ब्लेजर, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में पीएम से मिलने पहुंचे. वह पीएम के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे. पीएम मोदी भी हमेशा की तरह मुस्कुारते हुए विजय का स्वागत किया. सामने आई तस्वीरें देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों नेताओं की गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है.

सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि साल 2014 में भी विजय और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी.

सूत्र बता रहे हैं कि करीब दो साल बाद पीएम मोदी और थलापति विजय की मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट मीटिंग होने की बात कही जा रही है. इस मुलाकात को लेकर इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि इस वक्त थलापति विजय कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार चला रहे हैं.

काकोली घोष दस्तीदार कौन हैं? TMC सांसद ने सभी पदों से इस्तीफा देकर ममता दीदी को दिया तगड़ा झटका

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से अचानक इस्तीफा दे दिया है। घोष दस्तीदार का इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जब पार्टी पहले से ही नेताओं के दूसरे दलों में जाने की चुनौती का सामना कर रही है।

बारासात से प्रतिनिधित्व करने वाली दस्तीदार ने इस फैसले के पीछे "व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं" का तर्क दिया है लेकिन , राजनीतिक गलियारों में यह इस्तीफा भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से उनकी हालिया मुलाकात से जोड़ा जा रहा है, जिसने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है।

जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बसें होंगी उपलब्ध सीएम योगी

जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊ, जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया।

अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं तथा वर्ष 2030 तक 10 हजार चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक लगभग 2500 चार्जिंग स्टेशन संचालित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगी। उन्होंने भूमि अधिग्रहण और विनिमय संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि फरुर्खाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 55 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक

एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट स्वीकृत हो चुका है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और निवेशकों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। डेवलपर चयन के लिए निविदा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 जुलाई 2026 कर दी गई है। वहीं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 हेक्टेयर में से 144 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो चुकी है तथा शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश अनुकूल व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि भवन स्वीकृति संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर 136 रिक्त पदों में से 40 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा शेष 96 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिला एवं विकासखंड स्तर पर 360 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है।

उन्होंने लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल पार्क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को प्रदेश के कृषि और औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ाया जाए। बैठक में बताया गया कि सीड पार्क परियोजना के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और प्रमुख बीज कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है ।

इबोला की वैक्सीन हो गई तैयार! किसने की इजाद और कैसे मिलेगी? कितनी असरदार?

जहां दुनिया एक तरफ इबोला वायरस के डर में जी रही है तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी देशों में इसे लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक के डेटा के मुताबिक सेंट्रल एशिया में 241 लोग इससे जान गंवा चुके हैं जबकि इससे कितने प्रभावित हैं, कुछ पता नहीं। ये वायरस कोरोना जैसी तेजी से फैल रहा है लेकिन उससे बड़ा खतरा है इसका मृत्यु दर, जहां इसमें 50 प्रतिशत संभावना है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है, जो कोरोना में 2 प्रतिशत तक थी। इसी बीच एक राहत भरी खबर आ रही है।

'चुनाव में भाजपा को अच्छे से धो-पटककर सुखा देगी जनता'

अखिलेश ने सीएम योगी के बिजली के तार वाले बयान पर किया पलटवार

(जीएनएस)।

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा सरकार में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने वाले बयान पर पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने बुधवार को एक्स पर लिखा,'अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो-पटककर हमेशा के लिए सुखा देगी। शुक्र है उप्र के असफल मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि इस महा विद्युत आपदा के पीछे दिल्लीवालों के भेजे हुए दूत की साजिश है।'

सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, ये स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते हैं। अगर आते हैं तो माननीय से अनुरोध है कि उनके 'कंधे पर हाथ रखकर' एक तस्वीर आप पोस्ट कर दीजिए, जनता को आपकी 'आपसी गर्मी' से तो राहत मिल जाएगी, क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी एकांत में साथ देखा नहीं।

'मजबूत संगठन से बनेगा बेहतर समाज', लखनऊ में मोहन भागवत का स्वयंसेवकों को संदेश, शाखा विस्तार को बताया जरूरी

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत तीन दिवसीय लखनऊ प्रवास के बाद दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने फरर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों को संगठन मजबूती, शाखा विस्तार और समाज निर्माण का संदेश दिया।

लखनऊः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फरर) के सरसंघचालक मोहन

भागवत तीन दिवसीय लखनऊ प्रवास के बाद मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने संघ के कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों को संगठन की मजबूती, शाखा विस्तार और समाज निर्माण का संदेश दिया। इसके साथ ही संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ शताब्दी वर्ष के अभियानों की समीक्षा कर भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 20 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग 21 मई से सरस्वती शिशु मंदिर, निराला नगर में आयोजित किया जा रहा है, जो 11 जून तक चलेगा। इसी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख 24 से 26 मई तक लखनऊ में रहे।

प्रवास के दौरान उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का मूल उद्देश्य बेहतर और संगठित समाज का निर्माण करना है। इसके लिए प्रतिबद्ध और वैचारिक रूप से मजबूत कार्यकताओं की जरूरत होती है।

अपने बौद्धिक प्रबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण वर्ग स्वयंसेवकों को मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाते हैं।

सम्पादकीय

क्वाड विदेशमंत्रियों ने विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण पर किया एतराज

क्वाड यानि चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद के विदेश मंत्रियों की संपन्न हुई मंगलवार की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने इस संगठन की और अधिक प्रासंगिक, सार्थक और सक्रिय साबित करते हुए हिन्द प्रशान्त क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक स्वर में आ'ान किया।

दरअसल यह बैठक चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जल्द ही होने वाली शिखर बैठक में भूराजनीतिक दृष्टि से नई दिशा का निर्धारण करने वाले फैसलों की पृष्ठभूमि है। उल्लेखनीय है कि इस वक्त क्वाड की अध्यक्षता भी भारत के पास ही है इसलिए विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ही इस बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड के विदेशमंत्रियों ने दुनिया भर में ईंधन के लिए मचे हाहाहकार के लिए प्रमुख कारण होर्मूज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को रोकने और भारी भरकम टैक्स ठोंकने को भी प्रमुख कारण माना। क्वाड विदेशमंत्रियों ने चीन को भी संदेश देते हुए कहा कि हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाली, बल प्रयोग या दबाव बनाने वाली हर अस्थिरकारी या एकतरफा कार्रवाईं का कड़ा विरोध दोहराते हैं।" असल में क्वाड अपतटीय संसाधनों के विकास हस्तक्षेप, नववाहन या उड़ान भरने की स्वतंत्रता में बार-बार बाधा डालने तथा सैन्य विमानों, तटरक्षक और समुद्री मिलीशिया पोतों की खतरनाक और दबावपूर्ण कार्रवाईंयों को लेकर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हैं। क्वाड विदेशमंत्रियों ने विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण पर भी एतराज किया। सच तो यह है कि क्वाड कोई सैन्य संगठन नहीं है जो किसी देश को निशाने पर लेकर उसे तबाह करने की रणनीति पर विचार करे। सच तो यह है कि क्वाड एक सकारात्मक संगठन है जो किसी भी तरह के विस्तारवाद-दादागिरी का जमकर विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि क्वाड कोई ऐसा संगठन है जो किसी, देश को निशाना बनाने के लिए बना है किन्तु यह भी है कि यदि कोई देश दादागिरी करता है तो सदस्य देश आवाज उठाते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि कोई देश अपनी विस्तारवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर भूराजनीतिक परिस्थिति को तनावग्रस्त न करे। बहरहाल क्वाड देशों की एकजुटता का लाभ भी दिख रहा है। भारतीय प्रशांत क्षेत्र में अराजकता नहीं दिख रही है। यदि क्वाड प्रयास करे तो संभव है कि होर्मूज जलडमरूमध्य से दुनिया के सभी देशों के जहाजों को रास्ता मिल सकता है। लब्बोलुआब यह है कि क्वाड ने आज जो सक्रियता दिखाने का संकेत दिया है, वह निश्चित रूप से इस संगठन की प्रासंगिकता, वैचारिक एकरूपता और चुनौतियों से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही क्वाड की सदस्यता के लिए जिस तरह से वुछ देश लालायित हैं, उससे भी लगता है कि इस संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सक्रियता एवं सार्थक प्रयासों के कारण जनाकांक्षाओं की पूर्ति का शक्ति केन्द्र बन सकता है।

भारत के खिलाफ 'यूक्रेन मॉडल' अपनाने की फिराक में पाकिस्तान, एक्सपर्ट ने दी रूस वाली गलती से बचने की सलाह

(जीएनएस)।

मई 2025 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने कई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है जिनमें अब्दाली, फतह-4, तैमूर और फतह-क्क शामिल हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक और तरीका है जिससे इस्लामाबाद भारत के रणनीतिक फायदे को उसकी रणनीतिक कमजोरी में बदल सकता है।

यूक्रेन के ड्रोन युद्ध के सामने बेबस पाकिस्तान

इस्लामाबादः भारत ने पिछले साल मई महीने में हुए संघर्ष के दौरान अपनी रणनीतिक गहराई का फायदा उठाते हुए आधे घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का लंबा और संकरा आकार होने की वजह से उसके पास रणनीतिक गहराई नहीं है। पाकिस्तान की पूर्व-पश्चिम में अधिकतम चौड़ाई अपने सबसे चौड़े बिंदु पर सिर्फ 1,125 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि देश का अधिकांश हिस्सा भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों की मारक सीमा के भीतर आता है। खुद पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कह रखा है कि आतंकवादियों को "छिपने के लिए एक इंच जगह भी नहीं मिलेगी" और उन्होंने यह भी जोड़ा कि "आतंकवादियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी यहां तक कि पाकिस्तान सेना की पनाह में भी नहीं।"

दूसरी तरफ भारत के पास काफी अंदर तक रणनीतिक गहराई और भौगोलिक फायदे हैं। भारत की पूरब से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई लगभग 2,933 ᵏ है जो पाकिस्तान की चौड़ाई से दोगुनी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान इस असंतुलन से अच्छी तरह वाकिफ है। अगस्त 2025 में फ्लोरिडा के टैम्पा में एक निजी डिनर कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान भारत को पूरब से पश्चिम तक निशाना बनाएगा। उनकी इन टिप्पणियों का मकसद नई दिल्ली को यह संदेश देना था कि उसे अपने बड़े भूभाग की वजह से सुरक्षा का कोई गलत एहसास नहीं पालना चाहिए।

मई संघर्ष के बाद पाकिस्तान के बड़े मिसाइल टेस्ट

मई 2025 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने कई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है जिनमें अब्दाली, फतह-4, तैमूर और फतह-क्क शामिल हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक और तरीका है जिससे इस्लामाबाद भारत के रणनीतिक फायदे को उसकी रणनीतिक कमजोरी में बदल सकता है। सच तो यह है कि यूक्रेन पहले से ही दुनिया को यह दिखा रहा है कि किसी देश का आकार उसकी रणनीतिक कमजोरी कैसे बन सकता है।

रूस के अंदर गहराई तक कैसे हमले कर रहा यूक्रेन

पश्चिमी देशों ने जब यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने से इनकार कर दिया तब यूक्रेन ने नई रणनीति को तेजी से अपनाया। यूक्रेन ने हाल ही में अपनी

नई FP-5 FlÔmi»»fgo क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया है जिसकी मारक क्षमता 3,000 किलोमीटर है हालांकि रूसी इलाके के अंदर गहरे हमले करने के लिए कीव की पहली पसंद लंबी अभी भी दूरी के ड्रोन ही रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के सीजफायर के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन हमले किए जिससे पता चलता है कि उनके ड्रोन जखीरे लबालब भरे हुए हैं। रूस ने 13 मई से 14 मई के बीच दो दिनों में 1,567 हमलावर ड्रोनों की रिकॉर्ड-तोड़ बौछार की।

इसके जवाब में यूक्रेन ने 16-17 मई की रात को मॉस्को पर एक साल से भी ज्यादा समय का अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले में 600 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए इस हमले में मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल थे जिसमें रूसी राजधानी में तीन लोगों की मौत हो गई और बड़ी आग लग गई।

खास बात यह है कि मॉस्को न सिर्फ यूक्रेनी फ्रंटलाइन से 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर है बल्कि पूरे रूस में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं। यूक्रेन ने राजधानी में हमला कर अपनी क्षमता साबित कर दी है। रूस के अंदर हजोरों किलोमीटर अंदर और फ्रंटलाइन से काफी दूर किए गए ये सटीक हमले पांच अहम क्षमताओं को दिखाते हैं

1- बेहतरीन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना

2- 1,000 किलोमीर से ज्यादा की लंबी दूरी की ड्रोन टेक्नोलॉजी

3- आधुनिक गाइडेंस सिस्टम जिसमें GPS-रहित माहौल में अक-पावर्ड नेविगेशन

4- हाई-बैंडविड्थ सैटेलाइट कनेक्टिविटी

5- फर्स्ट-पर्सन-व्यू (FPV) कंट्रोल शामिल है।

भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने यूरेशियन टाइम्स में लिखा है "धीमी गति से उड़ने वाले यूक्रेनी ड्रोन हवाई सुरक्षा और दृश्य पहचान से बचने के लिए पृथ्वी की सतह के सबसे करीब (NOE) उड़ान भरते हुए और चालाकी से मार्ग बदलते हुए रूसी क्षेत्र में गहराई तक घुसपैठ करते हैं।" उन्होंने कहा "खबरों के मुताबिक वे आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ संचालन के लिए स्टारलिंक लो-लेटेंसी संचार नेटवर्क और नेविगेशन के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। जब भी जीपीएस या स्टारलिंक सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं तो ड्रोन अस्थायी रूप से एआई-आधारित स्वायत्त मशीन-विजन नेविगेशन पर लौट आते हैं। सैकड़ों, कभी-कभी एक हजार से भी ज्यादा किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद उन्हें गाइड करते हुए टारगेट पर सटकी हमला करने के लिए पहुंचाया जाता है।"

FPV ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक कैसे बना?

इजरायली कंपनी XTEND जिसके सिस्टम का इस्तेमाल IDF बड़े पैमाने पर करती है उसने यह साबित कर दिया है कि उसके FPV ड्रोन को दूसरे महाद्वीप से भी उड़ाया जा सकता है भले ही उसमें काफी ज्यादा देरी हो। अमेरिकी ड्रोन MQ-9 ReÔper को दुनिया में लगभग कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए कम देरी वाली सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ दूरियां और बड़े भूभाग अब बेमानी हो गए हैं। यहां तक कि जिस देश के पास लंबी दूरी की सटीक मिसाइलें नहीं हैं वह भी अपने दुश्मनों पर हजारों मील दूर से हमला कर सकता है। 'नैप-ऑफ-द-अर्थ' (NOE) उड़ान प्रोफाइल का उपयोग करके ड्रोन उन हवाई क्षेत्रों में भी घुसपैठ कर सकते हैं जिनकी हवाई सुरक्षा काफी एडवांस एयर डिफेंस करते हैं।

पाकिस्तान के 'यूक्रेन मॉडल' पर गंभीर नजर रखने की जरूरत

भारत को यूक्रेन मॉडल पर काफी गंभीकता से नजर रखने और अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। अगले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में, पाकिस्तान द्वारा भारत के अंदर गहरे हमले करने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन का उपयोग किए जाने की ज्यादा संभावना है। विजयेन्द्र के ठाकुर का मानना है कि पाकिस्तान लंबी दूरी के स्टील्थ ड्रोन का उपयोग कर सकता है और उन्हें ठडए प्रोफाइल में उड़ा सकता है। भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए अपरंपरागत रास्तों का उपयोग कर सकता है और भारत के रिएक्शन पर नजर रखने के लिए चीनी करफ संपत्तियों का लाभ उठा सकता है।

मोदी-योगी की जुगलबंदी है कमाल, 2027 में अखिलेश-राहुल-माया सबका होगा बंटाधार!

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव, यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरी बढ़ गई है. हालांकि जमीन पर दोनों नेताओं की मजबूत जुगलबंदी साफ दिखाई देती है. गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को डबल इंजन सरकार की सफलता के तस्वीर हैं. साथ ही उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान और ई-श्रम जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को यूपी में प्रभावी ढंग से लागू करने का श्रेय योगी सरकार को दिया गया है. लेख के अनुसार विपक्ष बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने में जुटा है, जबकि मोदी-योगी के बीच मजबूत तालमेल बना हुआ है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हवा बनने लगी है. आठ महीने से भी कम समय बचने के चलते बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल कील कवच दुरुस्त करने में जुट गए हैं. अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती की सक्रियता राज्य में बढ़ गई है. इसी बीच विपक्षी नेताओं खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया इंटरव्यू और बयानों पर नजर डालें तो वह एक नैरेटिव गढ़ने के प्रयास में दिखते हैं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच दूरी बढ़ी है. अखिलेश यादव अपने इंटरव्यू में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर तंज भरे लहजे में कहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली की दूरी बढ़ गई है.

राजनीति के कुछ जानकार भी इस नैरेटिव को मजबूत करने के प्रयास में दिखते हैं. खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष इस तरह के नैरेटिव को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देता दिख रहा है. जबकि धरातल पर नजर डालने पर कहानी बिलकुल उलट नजर आती है. दिखता है कि मोदी और योगी के बीच जबदरस्त जुगलबंदी है. साफ तौर से दिखता है कि इसी जुगलबंदी के चलते उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार का असली विकास दिखता है. यूं तो बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं के सामंजस्य के अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन आइए उन खास पर नजर डालते हैं जिसके जरिए जुगलबंदी को सरलता से समझा जा सकता है.

पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी और ड्रीम प्रोजेक्ट है. यह देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक है. यूपी सरकार की संस्था यूपीडा इस पूरे

प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है, जिसने जमीन अधिग्रहण से लेकर इसके निर्माण और देखरेख की पूरी जिम्मेदारी संभाली है. यह यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है. इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है. सीएम योगी चाहते तो इसका उद्घाटन खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया. पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल, 2026 को हरदोई में इस भव्य गंगा एक्सप्रेसवे के फेज-1 का आधिकारिक उद्घाटन कर इसे जनता के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया.

इसी तरह इसी मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते दिखे. इतना ही नहीं पिछले 10 साल में नोएडा और इसके आसपास के इलाकों में उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई है. केंद्र सरकार की मदद से कई देशी और विदेशी कंपनियां नोएडा में अपना प्लांट लगा चुकी हैं. इससे पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में ही दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल की सौगात दी गई. केंद्र सरकार की मदद का ही नतीजा है कि भारत में आज 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश में हो रही है. नोएडा में आईटी हब, एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल (एश), फिनटेक और डीप टेक के कई प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं.

केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अव्वल है यूपी

योगी और मोदी की जुगलबंदी का ही कमाल है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लागू करने में यूपी अव्वल राज्यों की श्रेणी में है. उज्जवला योजना हो चाहे गरीबों को पक्के मकान देने की बात हर क्षेत्र में सीएम योगी ने केंद्र की योजनाओं को बेहद सफलता पूर्वक धरातल पर उतारा है. उसी तरह 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकरण में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन है. निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख और दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है. इसी तरह श्रमिक की बेटी की शादी के लिए 65,000 से 75,000 रुपये तक की सहायता दी जा रही है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार, अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत वंचित तबके के बच्चों को विश्वस्तरीय और निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है. केंद्र सरकार की ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 7 लाख से अधिक श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है. अटल पेंशन योजना के तहत यूपी में 93 लाख लाभार्थी हैं.

डबल इंजन सरकार का फल है बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर अपने आप में केंद्र और राज्य सरकार की एकजुटता का उदाहरण है. यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र का औद्योगिक कायाकल्प करना है. केंद्र सरकार ने देश में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी- एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) के तहत कुल 6 नोड्स (Nodes) बनाए गए हैं, जिनमें से 2 प्रमुख नोड्स विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित हैं, पहला झांसी और दूसरा चित्रकूट.

वंदे मातरम पर मोदी-योगी दिखे साथ

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर 8 दिसंबर 2025 को विशेष और विस्तृत चर्चा आयोजित की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 'वंदे मातरम' पर जोरदार भाषण दिया. इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 22 दिसंबर 2025 वंदे मातरम के महत्व, इसके इतिहास और राष्ट्रीय चेतना पर बात करने के लिए सदन में करीब 5 घंटे की विशेष बहस कराई गई. विधानसभा में चर्चा के बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वंदे मातरम के संपूर्ण छंद का गायन अनिवार्य कर दिया.

मोदी की मदद से यूपी में नये आर्थिक प्रोग्रेस का रिकॉर्ड बना रहे योगी

पिछले साढ़े नौ साल में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों की लिस्ट में आ गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसडीपी के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. 25 करोड़ की जनसंख्या और 56 फीसदी कार्यशील आयु वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े श्रम एवं उपभोक्ता बाजारों में से एक बन चुका है. केंद्र सरकार की ओर से मिले बजट और यूपी सरकार की ओर से जुटाए गए संसाधनों के चलते मौजूदा वक्त में 22 एक्सप्रेसवे, 16 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और पूर्वी व पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं या इसपर तेजी से काम चल रहे हैं.

इसके अलावा अयोध्याजी, वाराणसी जैसे धार्मिक नगरी में जितनी भी विकास कार्य की योजनाएं चल रही हैं उसमें हर जगह केंद्र और राज्य सरकार की एकजुटता नजर आती है. विपक्षी दलों के साथ दिक्कत ही यही है कि वह अपने संगठन पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते रहते हैं. हालांकि पिछले 10-12 साल में विपक्ष का झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने में हमेशा से मुंह की खानी पड़ी है. फिर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं. अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर से मोदी-योगी के बीच दूरी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इसमें तनिक भी सच्चाई नजर नहीं आती है.

पीएम मोदी के आह्वान का असरः सोने को छोड़ पीतल नगरी के 'गोल्डन' गहनों पर रीझीं महिलाएं, बिक्री कई गुना बढ़ी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक सोना न खरीदने के किए गए आ'ान और आसमान छूती सोने की कीमतों का असर अब साफ दिखने लगा है. बाजारों में सोने की खरीदारी में आई कमी के बीच एक नया ट्रेंड सामने आया है. महिलाएं अब असली सोने की जगह, हूबहू सोने जैसी दिखने वाली पीतल की ज्वेलरी को अपनी पहली पसंद बना रही हैं. पीतल नगरी में बड़े पैमाने पर मिलने वाली यह ज्वेलरी न सिर्फ जेब पर हल्की है, बल्कि लुक में बिल्कुल 'प्योर गोल्ड' को मात देती है. यही वजह है कि इसकी डिमांड और बिक्री में अब कई गुना का बंपर उछाल आ गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष तक सोना न खरीदने का आ'ान किया था, जिसको लेकर लोगों ने सोने की खरीदारी कम कर दी है. तो वहीं अब सोने की जगह महिलाएं सोने जैसी दिखने वाली धातु यानी पीतल की ज्वेलरी खरीदना ज्यादा पसंद कर रही हैं. यह ज्वेलरी देखने में बिल्कुल सोने

की तरह होती है, जिसकी वजह से महिलाएं अब सोने की जगह इस ज्वेलरी का ज्यादा प्रयोग कर रही हैं. पीतल नगरी में बड़े पैमाने पर पीतल की यह ज्वेलरी मिल रही है.

सोने के बढ़ते दाम और 'पीतल ज्वेलरी' की भारी डिमांड

पीतल की ज्वेलरी के कारोबारी मोहम्मद फैसल ने बताया कि हमारे यहां पीतल की ज्वेलरी में पीतल के बैंगल्स, नेकलेस, चूड़ी, रानी हार, चेन सहित जितनी भी ज्वेलरी होती है, सभी मौजूद रहती है. जब से सोने के रेट बढ़े हैं, तब से महिलाएं इस ज्वेलरी को बहुत पसंद कर रही हैं. इसके अलावा पीएम मोदी ने भी 1 साल तक सोना न खरीदने का आवाहन किया था, जिसके बाद महिलाएं सोने की जगह पीतल की ज्वेलरी को ज्यादा पसंद कर रही हैं और पीतल की ज्वेलरी की जमकर डिमांड आ रही है और बिक्री भी हो रही है.

मात्र 50 रुपये से शुरूआत, दूर-दूर से पहुंच रहे खरीदार

उन्होंने कहा कि इसकी कीमत भी बहुत कम रहती है, 50 रुपये से पीतल की ज्वेलरी की कीमत शुरू होती है. बाकी अलग-अलग साइज और अलग-अलग डिजाइन पर निर्भर करती है, लेकिन यह कीमत 1000 या 2000 रुपये तक ही सीमित रहती है. पीतल की ज्वेलरी बिल्कुल गोल्ड की कॉपी है और देखने में बिल्कुल सोने की तरह दिखती है, जिसकी वजह से महिलाएं इसे ज्यादा खरीद रही हैं. पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी पीतल की ज्वेलरी सेल होती थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब कई गुना ज्यादा सेल बढ़ गई है और महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद रही हैं. उन्होंने कहा कि इसे खरीदने के लिए उत्तराखंड, रामनगर, काशीपुर सहित दूर-दूर के लोग आते हैं और जमकर खरीदारी करते हैं.

लोगों की जॉब छीन एआई को काम सौंपा, अब खर्चा देख कंपनियों के हाथ-पैर फूल रहे

Uber का साल भर का AI बजट सिर्फ चार महीने में खत्म हो गया. अब उसके सीओओ को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. माइक्रोसॉफ्ट भी अपने कर्मचारियों से एआई का कम इस्तेमाल करने के लिए कह रहा क्योंकि खर्च ज्यादा हो रहा है.

(जीएनएस)।

Uber के COO Andrew Macdonald को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी कंपनी में जो पैसा AI पर लगाया, वो सही था या आधा सही. दरअसल कंपनी का 2026 का पूरा

एआई बजट सिर्फ चार महीने में खत्म हो गया है. एआई पर कंपनी ने जितना पैसा लगाया, उसके हिसाब से कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है. माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ ऐसी समस्या से जूझ रहा है. उसने अपने कर्मचारियों से एआई का कम इस्तेमाल करने को कहा है क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा है. माने जिस खर्चे को बचाने के लिए कंपनियों ने कर्मचारी निकाले और उसके बदले एआई को रखा, वो अब हाथी पालने जैसे हो गया है.

क्या एआई का फुग्गा फूट गया है

एकदम नहीं क्योंकि अब फुग्गे में हवा ही पूरे तरीके से नहीं भरी गई तो फूटेगा कैसे. एआई बिला शक कमाल की चीज है मगर टेक कंपनियां उसको बंदर के हाथ में उस्तरे के जैसे इस्तेमाल कर रही हैं. ना सोचा, ना समझा, बस हर जगह एआई घुसेड़ दिया. सिस्टम में एआई लगाना कोई सस्ता सौदा नहीं है. इसके लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है.

आप एकदम ठीक पढ़े. आपके पास जो चैटजीपीटी या Claude ऐप है वो बेसिक वर्जन है जो ज्यादातर समय आपकी बे सिर पैर की बातों का जवाब देता है. कंपनी के सिस्टम में फिट करने के लिए इसका पेड वर्जन चाहिए होता है जो बहुत महंगा है. एआई को अपने सिस्टम में फिट करने में ऊबर सबसे आगे है. उसके पूरे सिस्टम में अब काम एआई एजेंट के जरिए हो रहा है मगर इसकी लागत अब उसके हाथ से निकल रही है.

बॉट की बात महंगी पड़ रही है

बात ऊबर या माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है. कई सारी कंपनियों ने कस्टमर केयर में इंसानों की जगह एआई बॉट बिठा दिए हैं. इन बॉट से बतियाना अब महंगा पड़ रहा है. कुछ महीने पहले Accenture ने 11,000 लोगों की छंटनी करके 8900 करोड़ बचाने का सोचा, मगर उनके फाइनल सेटेलमेंट में उसके 19000 करोड़ खर्च हो गए. बोले तो जितने के ढोल नहीं, उतने के मजीरे फूट गए.

पैसे से इतर एआई एजेंट गड़बड़ी भी खूब कर रहे हैं. अमेजन के सिस्टम में इन्होंने ऐसा झोल किया कि उसका शॉपिंग ऐप बिगड़ गया. कंपनी ने परेशान होकर अब एआई के ऊपर दो इंसानी मैनेजर बिठाए हैं.

महिला ने निजी इस्तेमाल के लिए मंगाया सामान, देखते ही डिलीवरी बॉय ने किया भद्दा कमेंट, बोला- 'मेरे रहते इसकी...'

(जीएनएस)।

ब्लिंकिट से प्राइवेट प्रोडक्ट मंगाने वाली एक महिला ने डिलीवरी एजेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. महिला की पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर बहस तेज हो गई है.

आज के दौर में ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. खाने-पीने की चीजों से लेकर दवाइयों और पर्सनल प्रोडक्ट्स तक, लोग घर बैठे सबकुछ ऑर्डर कर लेते हैं. खासतौर पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी है.

लेकिन हाल ही में एक महिला के साथ डिलीवरी के दौरान जो घटना हुई, उसने महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि ब्लिंकिट के एक डिलीवरी पार्टनर ने उसके साथ बेहद आपत्तिजनक व्यवहार किया. महिला का कहना है कि यह अनुभव उसके लिए काफी डरावना और परेशान करने वाला था, क्योंकि डिलीवरी एजेंट उसके घर का पता भी जानता था.

महिला के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 1:35 बजे हुई, जब उसने ब्लिंकिट से एक सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट ऑर्डर किया था.

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊ की श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत में पुलिस का एक्शन, पति भूपेंद्र और ससुर कौशलेंद्र प्रताप सिंह को किया गिरफ्तार

(जीएनएस)।

लखनऊ। भोपाल की ट्विशा शर्मा जैसा मामला लखनऊ में भी सुर्खियों में हैं। यहां के ठाकुरगंज में 29 वर्ष की बैंकर श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत के प्रकरण में श्वेता सिंह के पति भूपेंद्र और ससुर कौशलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

श्वेता के पिता ¨ उमेश सिंह ने उसके पति के साथ ही सास-ससुर और देवर के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। श्वेता का विवाह महज छह महीने पहले हुआ था। उसके परिवार के लोगों को का आरोप है कि श्वेता को दस लाख रुपये और स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।

हरदोई रोड के विश्वास नगर निवासी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि बीते वर्ष नवंबर में 26 वर्षीय बेटी श्वेता सिंह का विवाह काशी विहार निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह से किया था। वह लालकुआं पर पैथालाजी चलाते हैं। पिता ने बताया कि रविवार रात श्वेता ने अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात की थी तो उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक था। कुछ ही देर बाद कौशलेंद्र ने फोन कर बताया कि श्वेता ने फंदे से लटककर जान दे दी है।

पिता का आरोप है कि ससुरालीजन शादी के बाद से ही कार की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। घटना के बाद खुद ही उसे लेकर अस्पताल भी पहुंच गए थे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। श्वेता की मां का हाल ही में आपरेशन हुआ है और वह प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पिता ने कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

श्वेता के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत के उसकी बहन कोमल और ज्योति ने पति भूपेंद्र और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वे लोग श्वेता से कहते थे कि तुम मेरे बेटे के पैर की धूल भी नहीं हो', वे श्वेता को परिवार से दूर करना चाहते थे। श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह हैगिंग बताई गई है। कोमल ने कहा कि भूपेंद्र तो श्वेता की 24 घंटे निगरानी करता था। मायके नहीं आने देता था, वह चाहता था कि श्वेता अपने परिवार से पूरी तरह कट जाए। वे लोग उससे कहते थे कि तुम मेरे बेटे के पैर की धूल भी नहीं हो।

जॉब छुड़ाकर बनाया हाउसवाइफ

श्वेता के परिवार के लोगों ने बताया कि वो एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम करती थी। शादी तय होते ही भूपेंद्र और ससुराल वालों ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। उन्होंने झूठा आश्वासन देकर कहा कि शादी के कुछ महीनों बाद फिर से कर लेना। श्वेता को पता ही नहीं था कि उसके ससुराल वाले उसे फुल टाइम हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहते हैं।

पैर पकड़ गिड़गिड़ाए थे पिता, वो खींच कर ले गया

श्वेता की दोनों बहनों ने बताया कि विदाई वाले दिन ही ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भूपेंद्र और पिता ने दस लाख रुपये और स्कॉर्पियो गांड़ी की मांग कर दी, कहने लगे हमें तुरंत चाहिए। हमने तो औकात से बढ़कर शादी की है और अब हमारे पास देने को कुछ और नहीं बचा है। यह बात कहते हुए पिता उनके सामने गिड़गिड़ाए। भूपेंद्र के पैर पकड़े और हाथ जोड़े, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। विदाई के समय उसने श्वेता को खींचते हुए कार में बैठाया और चला गया, हम लोगों को उससे मिलने तक नहीं दिया था।

सीएम योगी 29 मई को मऊ दौरे पर, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, मधुबन से सदर तक हाई अलर्ट

(जीएनएस)।

मऊः मऊ में 29 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री जिले के मधुबन और सदर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक विस्तृत प्रोटोकॉल प्रशासन को नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं। पिछले दो दिनों से अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पांति गांव पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मधुबन के गांधी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई सरकारी भवनों का उद्घाटन भी किया जाएगा और लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र व चेक वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मधुबन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बाहर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है और सुरक्षा में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है।

क्या बोले जिम्मेदार?

मधुबन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सदर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अधिकारियों के साथ लगातार ब्रीफिंग चल रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

शारीरिक संबंध बनाओ या ढाई लाख दो, नहीं तो वीडियो होगा वायरल

(जीएनएस)।

मछलीशहर। क्षेत्र के एक ग्रामीण बाजार की युवती से उसके इंस्टाग्राम दोस्त ने फोन कर कहा कि शारीरिक संबंध बनाओ या ढाई लाख रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। बार-बार दबाव बनाने और बदनामी से डरी युवती ने दोस्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती की प्रयागराज कमिश्नरेट के थाना बारा अंतर्गत कौझियारा कुबुद्दी गांव निवासी संदीप कुमार से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। युवती के अनुसार लगभग छह महीने पूर्व से युवक से इंस्टाग्राम पर चैटिंग होती थी। चैटिंग और वीडियो कॉलिंग का फायदा उठाकर युवक ने गलत तरीके से गंदा वीडियो बना लिया। उसके बाद युवक संदीप युवती से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। युवती के मना करने पर ढ़ाई लाख रुपये की मांग की। युवती का आरोप है कि न देने पर वीडियो परिजनों और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। घटना से परेशान युवती ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मछलीशहर कोतवाली प्रभारी विनीत राय ने कहा कि युवती की तहरीर पर आरोपी युवक पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

1180 करोड़ की कोकीन जब्त, ब्राजील से पहुंचा था गुजरात, 3 विदेशी गिरफ्तार

(जीएनएस)।

गुजरात के कच्छ तट पर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है। Gujarat Anti-Terrorism Squad और Indian Coast Guard के संयुक्त ऑपरेशन में करीब 1180 करोड़ रुपए कीमत की 118 किलो कोकीन जब्त की गई।

यह खेप ब्राजील से कई देशों और कराची होते हुए गुजरात पहुंची थी। मामले में अब तक तीन विदेशी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी समुद्र में कूदकर फरार हो गया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि भारत में यह ड्रग्स किस नेटवर्क तक पहुंचाई जानी थी।

मुंद्रा तट पर ऐसे पकड़ा गया जहाज

यह कार्रवाई गुजरात के मुंद्रा तट के पास की गई। अधिकारियों को पहले से सूचना मिली थी कि समुद्री रास्ते से बड़ी मात्रा में ड्रग्स लाई जा रही है। इसके बाद कोस्टगार्ड और अळर ने संयुक्त निगरानी शुरू की। संदिग्ध कंटेनर जहाज को समुद्री सीमा के भीतर ट्रैक किया गया। जहाज करीब 5 नॉटिकल मील दूर लंगर डाले खड़ा था। कई घंटों तक नजर रखने के बाद अधिकारियों ने

देखा कि जहाज से कुछ बैग समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जिसके बाद तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया।

तीन विदेशी आरोपी गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान जहाज पर मौजूद लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान एक आरोपी समुद्र में कूदकर फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। वहीं तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें क्लैविन चुकवुमा, ब्यारुहांगा जेम्स और जुम्मा नासिर उमर शामिल हैं। शुरूआती जांच में सामने आया है कि ड्रग्स की यह खेप दिल्ली के द्वारका इलाके तक पहुंचाई जानी थी। एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और भारत में मौजूद संपर्कों की जांच कर रही हैं।

ब्राजील से कराची होकर पहुंची खेप

जांच में पता चला है कि जहाज ब्राजील से निकला था और कई लैटिन अमेरिकी देशों, मेक्सिको, अमेरिका और कराची होते हुए गुजरात पहुंचा। इससे साफ है कि यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि पाकिस्तान के रास्ते इस नेटवर्क को कौन चला रहा था। अधिकारियों का मानना है कि समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर भारत में ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश लगातार बढ़ रही है, इसलिए तटीय सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है।

पहले भी पकड़ी जा चुकी है बड़ी खेप

गुजरात के समुद्री इलाके में इससे पहले भी कई बड़े ड्रग्स ऑपरेशन हो चुके हैं। अप्रैल 2025 में पोरबंदर के पास करीब 1800 करोड़ रुपए की 300 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। उस समय भी तस्करों ने समुद्र में पैकेट फेंककर भागने की कोशिश की थी। लगातार सामने आ रहे मामलों से साफ है कि गुजरात का समुद्री इलाका अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के निशाने पर है। एजेंसियों का कहना है कि आने वाले समय में समुद्री निगरानी और ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे।

भारत ने क्वाड से पिंड छुड़ाया, मतलबी दोस्तों के मतलब के लिए क्यों खुद को घसीटते रहें

(जीएनएस)।

भारत ने कूटनीतिक चालाकी दिखाते हुए क्वाड की कमान ऑस्ट्रेलिया को सौंपकर इस समूह से धीरे-धीरे अपना पिंड छुड़ा लिया है. बीते वर्षों में जिस तरह दुनिया के हालात बदले हैं, जिस तरह अमेरि¨ का मतलबी हुआ है, उससे क्वाड अपनी प्रासंगिकता खो चुका है. 'नेशन फर्स्ट' की नीति पर चलते हुए भारत अब पश्चिमी देशों के स्वार्थ के लिए खुद को घसीटने और उधार की दुश्मनी मोल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है.

आज यानी 26 मई, 2026 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में पूरी हो गई. चार्टर और कागजों पर तो कूटनीति पूरी हो गई, लेकिन सच ये है कि भारत ने क्वाड से पिंड छुड़ा लिया है. चार दस्तावेज जारी किए. क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी, इंडो पैसिफिक में निगरानी पर सहमति बनी. पश्चिमी एशिया का जिक्र भी आया. स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज से बिना टोल दिए आवाजाही पर बल दिया गया. लेकिन खबर ये नहीं है. खबर ये है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जिस मकसद से क्वाड का गठन किया, वो मकसद ही खत्म होता दिख रहा है. क्वाड के खात्मे की पटकथा लिख दी गई है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्वाड का बैटन पकड़ा दिया है. दिल्ली में इस साल होने वाली क्वाड नेताओं की शीर्ष बैठक शायद अब कभी न हो. इस लिहाज से हमने चालाकी से ऑस्ट्रेलिया को बागडोर थमाकर कूटनीति का शानदार नमूना पेश किया है.

2017 में क्वाड बना क्यों था? ये चीन की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए बना था. चार्टर में साफ था कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है लेकिन चीन को मैसेज देना था. इसकी जरूरत अमेरिका को थी. प्रशांत महासागर और एटालांटिक महासागर पार कर चीन तक पहुंचना उसके बूते की बात नहीं थी . अमेरिका को बैसाखी चाहिए था. ये बैसाखी भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान से बेहतर कौन दे सकता था. चीन से दो जंग लड़ चुके जापान में अमेरिकी बेस है. ऑस्ट्रेलिया का भूगोल साउथ चाइना सी के पास है. भारत तो चीन का भुक्तभोगी रहा है.

लेकिन पिछले 9 साल में दुनिया 360 डिग्री घूम चुकी है. हमारी चीन से लद्दाख और अरुणाचल में झड़प हो चुकी. उसके बाद रिश्ते वापस बेहतर हो रहे. ब्रिक्स समिट कजान में मोदी-जिनपिंग ने इसकी शुरूआत की. फिर 31 अगस्त, 2025 को चीन के तियानजिन में मोदी झ पुतिन और जिनपिंग की इस तस्वीर ने वॉशिंगटन तक कोहराम मचा दिया. दोनों देशों के बीच फ्लाइट शुरू हो चुकी है. एफडीआई में छूट देने की बात हो रही है. ये रिपोर्ट भी आ चुकी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए एक्स्ट्रा परमाणु पनडुब्बी मांगी जिसे देने से चीन ने मना कर दिया.

उधर ट्रंप ने क्या किया? पहले टैरिफ की लड़ाई लड़ी. 100 परसेंट से ज्यादा टैक्स लगा दिए। फिर खुद की हालत खराब हुई तो लाइन पर आ गए. आज बेसलाइन टैरिफ 25 परसेंट है. यूक्रेन वॉर में यूरोप से रिश्ते बिगाड़ लिए. धमकी देने लगे कि जी-2 बनेगा तो क्या होगा. ये दरअसल जी-7 और जी-20 के ठेंगा दिखाना था. मतलब था कि अगर चीन और अमेरिका एक हो जाएं तो..फिर अमेरिका ने ताइवान को डिफेंस एक्सपोर्ट रोक दिया. खुद बीजिंग पहुंच गए और सुनते रहे जब जिनपिंग ने अमेरिका को एक गिरता हुआ देश कह दिया. ट्रंप को महसूस हो गया कि चीन से बिगाड़ कर कुछ नहीं हो सकता. इसलिए ताइवान को भी त्याग दिया.

फिर ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी में चीन की दादागीरी हो या न हो, इससे अमेरिका को मतलब ही क्या रह गया? जब तुम्हें मतलब नहीं तो हमें उधार की दुश्मनी लेने की जरूरत क्यों है?

अमेरिका की उदासीनता पिछले दो साल में और ज्यादा बढ़ गई जब क्वाड की अध्यक्षता हमारे पास आई यानी भारत के पास आई. हम चारों सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इंतजार करते रहे लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. 2024 में बैठक होनी थी तो जो बाइडन ने तबीयत का बहाना बना दिया. बैठक विलमिंगटन में अपने होम टाउन में रखी. उसके बाद ट्रंप को टाइम नहीं है. उधर अपने को महाजन समझने वाला अमेरिका ब्रिक्स पर अटैक करता रहा जिसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है. बाद में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए. ट्रंप बार-बार आरोप लगाते हैं ब्रिक्स अपनी करेंसी लाएगा और डॉलर को रिप्लेस करने की साजिश रच रहा है. अरे भाई रूस हमारा टाइम टेस्टेड मित्र है. ईरान से पुराने रिश्ते रहे हैं. हम ग्लोबल साउथ के लीडर के नाते इस ग्रुपिंग को देखते हैं. इस पर रूस और चीन हमारे साथ है. तुम जब मर्जी ईरान से जंग शुरू कर दो, जब मर्जी वेनेजुएला पर अटैक कर दो, रूस पर बैन लगा दो और हम तुम्हारे डॉलर के भरोसे बैठे रहें. ये नहीं हो सकता.

ये भी एक बड़ा कारण है कि क्वाड को स्वाहा कर दिया जाए. ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई बहुराष्ट्रीय व्यवस्था गर्त में मिल जाएगी. इससे पहले भी लीग ऑफ नेशंस, सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन (सीटो) काल के गाल में समा चुके हैं. सबके पीछे एक कारण. प्रासंगिकता खत्म हो जाना. तो क्वाड की आयु दस साल की ही थी. अब हमारे लिए तो इसका मतलब खत्म है. और हम राष्ट्र प्रथम की राह पर हैं. मतलबी दोस्तों के मतलब के लिए कितना खुद को घसीटते रहें.

लखनऊ में चोरी की बिजली से होटल में चल रहे थे 13 एसी

10 लाख का भरना होगा जुमार्ना

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी में बिजली संकट के पीछे बिजली चोरी भी बड़ा कारण है। अमौसी जोन में बिजली संकट कम होते ही अभियंताओं की टीम घर घर चेकिंग करने में लग गई है। ऐसे ही उपभोक्ताओं को चिन्हित करने का काम अमौसी जोन के निलमथा में अधिशासी अभियंता एके शुक्ला ने किया। शुक्ला ने टीम के साथ एक निजी होटल में जांच की तो यहां बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी देखकर भौचक्के रह गए।

परिसर में तेरह एसी मिले और एक दर्जन पंखे व अन्य उपकरण चलते हुए पाए गए। टीम ने मौके पर ही 2.80 लाख का शमन शुल्क और दस लाख रुपये से अधिक का जुमार्ना

वसूलने की तैयारी कर ली है। वहीं बिजली चोर पर चोरी की धाराओं में मामला भी दर्ज करते हुए कनेक्शन काट दिया गया है। उधर अधिकारियों और कर्मचारियों की संभावित मिलीभगत की भी जांच शुरू कर दी गई है।

टीम ने छापा का समय मंगलवार रात का चुना। टीम यहां 10.20 बजे पहुंची। जांच के दौरान 28 किलोवाट लोड पर बिजली चोरी पाई गई। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार ने बताया कि नीलमथा के डिप्टीगंज हरिहरपुर आदर्शनगर स्थित होटल मिराकी इन में छापा मारा। प्रकाशनी शेखर के इस होटल में घरेलू बिजली से होटल चलता पाया गया, जिसमें नौ किलोवाट का कनेक्शन था।

होटल संचालक श्री फेज केबल को छज्जे के अंदर काट करके उसमें दूसरी केबल को जोड़कर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। जांच में दो मंजिल के होटल में 12 पंखे और 13 एसी चोरी वाली बिजली से जुड़े पाए गए। जांच दल में एसडीओ आशुतोष वर्मा, जेई राजेश कुमार, इंसपेक्टर वीरेंद्र सिंह आदि शामिल थे।

बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं! सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री की सख्ती का दिखा असर, गस्त करते नजर आए अधिकारी

सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री ने बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। इसके बाद मऊ में बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीण अंचलों में गश्त करते नजर आए।

(जीएनएस)।

मऊः भीषण गर्मी में बिजली कटौती के खिलाफ हर तरफ आवाजें उठ रही हैं। इसको लेकर कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने एक बैठक के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी कीमत पर बिजली की कटौती को बर्दश्त नहीं किया जाएगा।

गश्त करते नजर आए बिजली विभाग के अधिकारी

सीएम योगी ने कहा कि उपभोक्ता हितों में निर्बाध बिजली आपूर्ति विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। इसको लेकर अब बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अब पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। इसके नतीजन देर रात लगभग ग्यारह बजे जनपद मऊ के विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता महेश विश्वकर्मा बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीण अंचलों में गश्त करते नजर आए।

'निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रतिबद्ध है ऊर्जा विभाग'

रात्रि गश्त के दौरान विद्युत ट्रांसफॉमेरों और बिजली आपूर्ति का जायजा लेने पहुंचे अधिशासी अभियंता महेश विश्वकर्मा ने नवभारत टाइम्स से विशेष बातचीत में कहा कि उपभोक्ता बंधुओं के हित में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए हमारे बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे लोगों के बीच में लगे हुए हैं। जिससे किसी भी प्रकार से विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो। हम लोग निरंतर विद्युत ट्रांसफॉमेरी की स्थिति का जायजा भी ले रहे रहे हैं। इसके साथ ही उपभोक्ताओं और विद्युत कर्मियों से बातचीत करके हम ट्रिपिंग के कारणों को भी जानने का प्रयास कर रहे है,जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।

'प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं'

बातचीत के दौरान महेश विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई बिजली संकट नहीं है। ट्रासफार्मरों में ओवर हीटिंग के कारण समस्याएं ना आयें इसके लिए रोस्टर प्लान के हिसाब से उपभोक्ता बंधुओं को बिजली आपूर्ति की जा रही है। जिससे उन्हें निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे।

आवश्यकता अनुसार ही बिजली का करें इस्तेमाल

नवभारत टाइम्स से विशेष बातचीत में महेश विश्वकर्मा ने ट्रिपिंग के कारणों पर भी विशेष चर्चा की। उन्होंने बताया कि शाम के समय लगभग दस बजे तक उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली की पीक डिमांड होती है। जिसके कारण इस समय ट्रिपिंग की समस्या विशेष तौर से देखने को मिलती है।

'एक साथ सारे उपकरणों का प्रयोग न करें'

महेश विश्वकर्मा ने कहा कि अगर हमारे उपभोक्ता साथी चाहें तो आवश्यकता के अनुसार बिजली का प्रयोग कर इस ट्रिपिंग की समस्या से भी मुक्ति पा सकते हैं। एक साथ ही घर में लगे बिजली के सारे उपकरणों का प्रयोग ना करते हुए अगर इसे आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक तरफ जहां बिजली की बचत होगी वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉरमरों पर ज्यादे लोड भी नहीं पड़ेगा। इससे ट्रिपिंग की समस्या में कमी आ जाएगी।

अधिकारियों ने ट्रांसफॉर्मरों का किया निरीक्षण

देर रात हुई बिजली विभाग की गस्त में बिजली विभाग के अधिकारियों ने जनपद मऊ के वितरण खंड द्वितीय के सभी उपकेंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे कुछ ट्रांसफॉमेरों का निरीक्षण किया। यहां पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठीक पायी गई।

योगी सरकार के फैसले से गाजीपुर के ग्राम प्रधानों में खुशी की लहर, मिठाई बांट जताया आभार

(जीएनएस)।

गाजीपुर। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें आगामी छह माह तक प्रशासक नियुक्त किए जाने के शासन के निर्णय से क्षेत्र के प्रधानों में खुशी की लहर दौड़ गई।

बुधवार को प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रणजीत सिंह धर्मेंद्र के नेतृत्व में ब्लॉक परिसर में प्रधानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तथा प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया।

प्रधानों ने कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के कारण कई विकास योजनाएं अधूरी रह गई थीं। अब छह माह तक प्रशासक के रूप में कार्य करने का अवसर मिलने से गांवों में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कराया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि पंचायतों में सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन तथा अन्य जनहित की योजनाओं को गति मिलेगी।

ब्लाक अध्यक्ष रणजीत सिंह धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया यह निर्णय ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

इससे गांवों में चल रहे विकास कार्य बाधित नहीं होंगे और जनता को योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधान गांव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और सरकार ने गांवों के विकास को ध्यान में रखते हुए सराहनीय निर्णय लिया है।

प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष रवींद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों की समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक फैसला लिया है। इससे पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी तथा ग्रामीण विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।

जयराम यादव, बृजेश यादव, हरेंद्र विश्वकर्मा, बूच्ची यादव, सुरेंद्र यादव, सोनू गुप्ता, राजेश राम, मधु, हीरामणि चौहान, दिलीप कुमार, धनी यादव, जवाहर बिंद तथा राम लक्ष्मण राजभर मौजूद रहे।

राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद आरोपी

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम इलाके में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. दोपहर 1.00 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह को गंभीर हालत में पीजीआई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही संदीप सिंह के परिवार में कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में परिजन और परिचित पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंच गए.

पीजीआई पुलिस के मुताबिक मृतक संदीप सिंह मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे. वर्तमान में पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिंदी पार्क के पास रहते थे. संदीप सिंह का ऑफिस कल्ली पश्चिम इलाके में है. बुधवार दोपहर वह अपनी कार से ड्राइवर के साथ ऑफिस पहुंचे थे. कार से उतरकर जैसे ही पैदल वह ऑफिस की ओर बढ़ने लगे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उतरकर गोलियों की बैछार कर दी. गोली लगते ही संदीप नीचे गिर गए.

बदमाशों ने इसके बाद नजदीक से उनके सिर पर फायर कर दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. जिसकी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. दो युवकों ने दुःसाहसिक वारदात को दिनदहाड़े अंजाम दिया. जिससे पूरे मार्केट में दहशत का माहौल बन गया. प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह अपने पीछे पत्नी प्रीति बेटा सार्थक और एक बेटी को छोड़कर चले गए.

डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीजीआई थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक को गोली मार दी गई है, जो घायल अवस्था में पड़ा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस में घायल को इलाज के लिए पीजीआई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. वहीं सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिख रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा.

'मेरे पूर्वज हिंदू', ख्वाजा आसिफ का कुबूलनामा, कहा- पाकिस्तानी बच्चे गलत इतिहास पढ़ रहे

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ही देश के इतिहास लेखन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों को असली इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा और आधे पाकिस्तानियों को यह यकीन दिलाया गया है कि उनके पूर्वज अरब या ईरान से आए थे.

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान में पहचान और इतिहास को लेकर नई बहस छेड़ दी है. आसिफ ने खुलकर स्वीकार किया कि पाकिस्तान के बच्चों को "गलत इतिहास" पढ़ाया जा रहा है और देश के लोग अपनी असली जड़ों से दूर होते जा रहे हैं.

एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, "हम पाकिस्तानी मुसलमान अपने हिंदू पूर्वजों से नफरत करते हैं. पाकिस्तान के आधे लोग झूठा दावा करते हैं कि उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे." उन्होंने कहा कि यह सोच जानबूझकर तैयार की गई ताकि पाकिस्तान की नई पीढ़ी अपनी सभ्यता की पहचान से कट जाए.

ख्वाजा आसिफ ने इतिहास की

किताबों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिंदू शासकों को इतिहास से लगभग मिटा दिया गया. उन्होंने कहा, "हमने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को इतिहास की किताबों से हटा दिया क्योंकि वे हिंदू थे." उन्होंने आगे कहा, "मेरे पूर्वज हिंदू थे. क्या इससे मैं कम पाकिस्तानी हो जाता हूं?" आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली किताबें ऐसे लोगों ने लिखीं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक खास मानसिकता में ढालने की कोशिश की.

पाकिस्तानी समाज की सोच बदली गई!

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका की लड़ाइयों में पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए समाज की सोच बदली गई और उसी हिसाब से इतिहास को पेश किया गया. उन्होंने कहा, "हमारे बच्चे तथ्यात्मक इतिहास नहीं पढ़ रहे. आज पाकिस्तान में कई लोगों को यह तक नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कौन थे."

ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब वह पहले से ही अमेरिका और इजरायल के मुद्दे पर विवादों में घिरे हुए हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजरायल को मान्यता देने की अपील की थी.

पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देगा- आसिफ

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिफ ने कहा था, "मुझे निजी तौर पर नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी बुनियादी सोच से टकराता हो." उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान का पुराना रुख आज भी कायम है और जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश नहीं बनता, तब तक इस्लामाबाद इजरायल को मान्यता नहीं देगा.

पाकिस्तान ने अपने 78 साल के इतिहास में कभी इजरायल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है. यहां तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी साफ लिखा होता है कि यह इजरायल की यात्रा के लिए मान्य नहीं है. आसिफ के बयान के बाद अमेरिका में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली. अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इजरायल के प्रति पाकिस्तान की सोच लंबे समय से नकारात्मक रही है और ऐसे में अमेरिका-ईरान या इजरायल से जुड़े मामलों में उसकी मध्यस्थता "समस्याओं से भरी" हो सकती है.

लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एमएड, एलएलएम और बीवीए परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर किए घोषित, देखें पूरी लिस्ट

(जीएनएस)। लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एम.एड, एलएलम, बीलिबएससी, बीवीए और बीएफए की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए केंद्रों का निर्धारण कर दिया है। संबंधित कॉलेजों के विद्यार्थी लवि की वेबसाइट के माध्यम से अपना परीक्षा केंद्र देख सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी की ओर से इसकी सूची जारी क दी गई है। एम.एड के लिए सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें लखनऊ विश्वविद्यालय, रामा महाविद्यालय चिनहट, गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज, कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज आलमबाग, दयानंद बछरावां डिग्री कॉलेज रायबरेली, आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर और एएनडी टीटी कॉलेज सीतापुर शामिल है। इन केंद्रों पर 19 कॉलेजों के छात्र-छात्राएं परीक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं।

इस पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए सात केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें लखनऊ विश्वविद्यालय, कालीचरण पीजी कॉलेज चौक, रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज चिनहट, आईटी कॉलेज, डॉ. भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी, श्री राम भजन सिंह महाविद्यालय खीरी और दयानंद बछरावां डिग्री कॉलेज रायबरेली शामिल हैं। इन केंद्रों पर नौ कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा देंगे

बीवीए और बीएफए के केंद्र

विश्वविद्यालय ने इसके लिए छह केंद्रों की सूची जारी की है, जिनमें लखनऊ विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस, गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज फैजाबाद रोड, टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, श्री कृष्ण दत्त एकेडमी वृंदावन योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी और रायल प्रूडेंस डिग्री कॉलेज खीरी शामिल हैं।

लवि में होंगी एलएलएम की परीक्षाएं

लवि ने एलएलएम परीक्षा के लिए अपने यहां सेंटर बनाया है। इसमें लवि के साथ शिया पीजी कॉलेज और सिटी एकेडमी लॉ कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा देंगे।

कश्मीर मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान संग जारी किया बयान, भारत बोला- किसी का दखल बर्दाश्त नहीं

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर हैं. उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग मुलाकात भी की. इस दौरान चीन और पाकिस्तान ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी किया. इस संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया गया.

(जीएनएस)।

भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर से संयुक्त रूप से जारी किए गए बयान को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया है. चीन-पाकिस्तान के इस संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया गया था. इस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है.

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू-कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में की गई अनावश्यक टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज किया है.

उन्होंने कहा कि भारत का रुख

इस मुद्दे पर पहले से ही स्पष्ट और स्थिर है और संबंधित पक्षों को यह अच्छी तरह पता है. उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं और इस पर किसी अन्य देश को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया चीन-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में कश्मीर और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का उल्लेख किए जाने के बाद आई है.

भारत ने सीपीईसी परियोजनाओं का भी विरोध किया, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं. भारत ने कहा कि ये परियोजनाएं भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं. इस संबंध में भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों के समक्ष कई बार आपत्तियां जताई हैं.

भारत सरकार ने चीन-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में ट्रांस बाउंड्री वॉटर रिसोर्स कोऑपरेशन के उल्लेख को भी खारिज किया और कहा कि दोनों देशों के बीच कोई साझा सीमा नहीं है इसलिए इस तरह के सहयोग का सवाल ही नहीं उठता. भारत ने यह भी दोहराया कि वह 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं देता.

बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर हैं. उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग मुलाकात भी की. इस दौरान चीन और पाकिस्तान ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी किया. इस संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया गया. चीन ने कहा कि यह विवाद पुराना है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए.

लखनऊः होटल की दूसरी मंजिल से फेंकी सीमेंट की भारी बोरी, नीचे गुजर रहे मारुति शोरूम मैनेजर के ऊपर गिरी, मौत

लखनऊ के चिनहट में एक निमार्णाधीन होटल की दूसरी मंजिल से लापरवाही से फेंका गया मलबे का भारी बोरा सर्विस मैनेजर अनूप सिंह के सिर पर जा गिरा, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी होटल मालिक को हिरासत में ले लिया है, जबकि पीड़ित परिवार ने सख्त कार्रवाई और आर्थिक मदद की मांग की है.

(जीएनएस)।

लखनऊ के चिनहट इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक निमार्णाधीन होटल की दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया मलबे से भरा बोरा सीधे एक शख्स के सिर पर जा गिरा. इस हादसे में मारुति शोरूम के सर्विस मैनेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद से मृतक के परिवार में चीख-पुकार मची हुई है. पुलिस ने आरोपी होटल मालिक को हिरासत में ले लिया है.

मूल रूप से देवरिया के कुंडौली गांव के रहने वाले अनूप कुमार सिंह (36) लखनऊ के आईटी चौराहा स्थित शोरूम में सर्विस मैनेजर थे. वह चिनहट के नौबस्ता कला स्थित वसुंधरा विहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे. मंगलवार सुबह करीब 8 बजे अनूप हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे. जैसे ही वह कॉलोनी में स्थित एक

होटल के सामने पहुंचे, तभी यह भयानक हादसा हो गया.

नौबस्ता कला में विशाल तिवारी का एक ओयो होटल है, जहां निर्माण कार्य चल रहा था. वहां रखी कुछ सीमेंट पानी पड़ने की वजह से जम गई थी. होटल मालिक विशाल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुबह सीमेंट के उस जमे हुए हिस्से को टुकड़ों में तोड़ा और मलबे को एक बोरी में भर लिया. इसके बाद बिना नीचे देखे लापरवाही से उस भारी बोरी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया.

होटल की दूसरी मंजिल से फेंकी गई मलबे की बोरी सीधे नीचे से गुजर रहे अनूप कुमार सिंह के सिर पर जा गिरी. मलबा इतना भारी था कि अनूप का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गए. आस-पास के लोगों ने आनन-फानन में उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

मृतक के भाई श्रेयांश ने बताया कि अनूप ही घर में अकेले कमाने वाले थे. उनके परिवार में पत्नी ऋचा के अलावा दो छोटे बच्चे (दिव्यांश और अयान) हैं, जिनमें से एक बच्चा तो महज 3 महीने का है. यही नहीं, उनके पिता भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. परिवार ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद की मांग की है.

मृतक के भाई का आरोप है कि हादसे के बाद होटल मालिक और उसके लोगों ने जमीन पर फैले खून को साफ कर सबूत मिटाने की कोशिश की. इतना ही नहीं, जब वे लोग थाने पहुंचे तो होटल मालिक के रसूखदार जानने वाले वहां आ गए और पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाने लगे.

घटना की सूचना मिलते ही चिनहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. चिनहट थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी होटल मालिक विशाल तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

शाहजहांपुरः स्वामी चिन्मयानंद ने दान की 550 करोड़ की संपत्ति, योगी सरकार की यूनिवर्सिटी के नाम की रजिस्ट्री

सीएम योगी के कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्वामी चिन्मयानंद ने कहा, संपत्ति सरकार को नहीं बल्कि समाज को समर्पित कर रहे हैं.

(जीएनएस)।

शाहजहांपुरः पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती बुधवार को शाहजहांपुर के रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे. उन्होंने यहां एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए मुमुक्षु आश्रम की 550 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी के नाम दान कर दी. स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज और मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता हैं.

स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बाद वे तहसील सदर के रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे थे.

रजिस्ट्री दफ्तर में प्रक्रिया पूरीः रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुमुक्षु आश्रम की 550 करोड़ की सारी संपत्ति यूनिवर्सिटी के नाम राज्य सरकार को सौंप दी. बायोमेट्रिक मशीन पर सिर्फ एक अंगूठा लगाते ही यह विशाल संपत्ति राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई. राज्यपाल की तरफ से उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली, प्रोफेसर सुधीर चौहान ने इस रजिस्ट्री को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया. इस ऐतिहासिक कदम के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मीडिया से भी बात की.

कट्टे की जगह हाथों में कलमः उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस डिग्री कॉलेज की शुरूआत की थी, तब यहां के युवाओं के हाथों में कट्टे हुआ करते थे. लेकिन आज उनके इस प्रयास और शिक्षा के प्रसार की वजह से युवाओं के हाथ में कलम है. यह संपत्ति वे सरकार को नहीं, बल्कि समाज के नाम समर्पित कर रहे हैं. इस यूनिवर्सिटी से शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा पाने के बाद अब क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.

ठुकराया कुलाधिपति का प्रस्तावः उन्होंने बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. स्वामी चिन्मयानंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इस नई यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, उन्होंने इस बड़े पद के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया. पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि वे सरकार से किसी बड़ी अपेक्षा की उम्मीद नहीं रखते हैं.

समाज के विकास के लिए कदमः उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जो समाज और देश की प्रगति के लिए सरकार को सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं. यह जनतंत्र का वरदान है कि जनता के हाथ में है कि वह सरकार को किधर ले जाना चाहती है और उससे क्या काम लेना चाहती है. जब पब्लिक का संगठन आगे आता है, तो सरकार भी उसकी खुलकर मदद करती है. अब धीरे-धीरे समाज के लोग आगे आ रहे हैं। और शिक्षा के प्रति लोगों में रुचि लगातार बढ़ रही है.

यूपी के इतिहास में पहली बार 57 हजार प्रधान बने प्रशासक, 2027 में सीएम योगी को मिलेगा 'रिटर्न गिफ्ट'

यूपी के इतिहास में पहली बार 57 हजार से अधिक प्रधान प्रशासक बने हैं. पंचायत चुनाव में देरी और प्रधानों के कार्यकाल खत्म होने के बाद योगी सरकार ने प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया है. जिसके बाद राष्ट्रीय प्रधान संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है. राष्ट्रीय प्रधान संघ ने कहा कि 2027 के चुनाव में प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिटर्न गिफ्ट देंगे.

(जीएनएस)।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्य के सभी 57,694 प्रधानों को अब प्रशासक के रूप में पदभार सौंप दिया गया है. यह फैसला योगी सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को निरंतर गति देने के उद्देश्य से लिया गया है. यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है. पंचायत चुनाव में देरी की वजह से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले का राष्ट्रीय प्रधान संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम प्रधान उन्हें रिटर्न गिफ्ट देंगे.

राष्ट्रीय प्रधान संघ ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया. संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों के साथ किए गए सभी वादों को पूरा किया है. पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रधानों को प्रशासक बनाकर सरकार ने एक नया उदहारण पेश किया है, जिससे गांवों में विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी. अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा, 'उट योगी ने ट्रिपल इंजन सरकार के वादे को निभाया है. प्रधानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई ऊंचाई देगा.'

2027 में 'रिटर्न गिफ्ट' का ऐलान

राष्ट्रीय प्रधान संघ ने स्पष्ट संदेश दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'रिटर्न गिफ्ट' देंगे. संघ के अध्यक्ष ने कहा, '57 हजार से ज्यादा प्रधानों की ओर से हम उट योगी का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने जो वादे किए थे, उन्हें न केवल पूरा किया बल्कि गांव स्तर पर विकास की मजबूत नींव रखी है. अब हमारी बारी है. 2027 में प्रधान पूरे समर्थन के साथ सरकार को वापसी का तोहफा देंगे.'

सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा. प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रधान अब भी गांवों के विकास कार्यों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा सकेंगे. राज्य सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का कार्य तेज गति से चलेगा.

72 घंटे में 70,000 गाड़ियां! शिमला में पैर रखने की नहीं बची जगह

(जीएनएस)।

उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही तेज गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव राजधानी शिमला (ग्रैं') में देखने को मिल रहा है, जहां बीते कुछ दिनों में पर्यटकों की भीड़ अचानक काफी बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि शहर की सड़कें लगातार वाहनों से भरी हुई हैं और कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है।

शिमला की संकरी सड़कों और सीमित पार्किंग व्यवस्था के कारण प्रशासन के सामने चुनौती और बढ़ गई है। बीते 24 दिनों में करीब 6.31 लाख

वाहन शिमला पहुंचे हैं, जबकि केवल पिछले 72 घंटों में ही लगभग 70 हजार गाड़ियां शहर में दाखिल हुईं। गर्मी का असर अभी और बढ़ने की संभावना है, इसलिए प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है। इसी वजह से पुलिस और प्रशासन ने अभी से विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं और पर्यटकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

अधिकारियों के मुताबिक, पिछले 24 दिनों में कुल 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। इनमें से करीब 3,70,000 वाहन चंडीगढ़-कालका मार्ग के जरिए शहर में दाखिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक किन्नौर, बिलासपुर और कुल्लू की तरफ से भी शिमला पहुंचे।